नेटबंदी के चलते 17000 किसान जमा नहीं करा पाये फसली ऋण

सरकार ने बढ़ाई फसली ऋण जमा कराने की अंतिम तिथि, बैंकों को नहीं मिले आदेश

झुंझुनूं, 13 जुलाई। नेट बंदी ने झुंझुनूं जिले के करीब 17 हजार किसानों को परेशानी में डाल दिया हैं। नेट बंदी की वजह से किसान तय तिथि को अल्पकालीन फसली ऋण जमा नहीं करवा पाए। हालांकि सरकार ने किसानों को राहत देते हुए ऋण जमा करवाने की अंतिम तिथि बढाई हैं। मगर आदेश नहीं आने के कारण अब किसानों को फसली ऋण के साथ ब्याज और पेनल्टी जमा करवानी पड रही है। अल्पकालीन फसली ऋण चुकाने वाले किसानों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। राज्य सरकार ने फसली ऋण जमा कराने की अंतिम तिथि तो बढा दी। लेकिन सहकारी बैंकों को आदेश जारी नहीं किए गए हैं। झुंझुनूं जिले के 84023 किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण जारी किया था। इस लोन को 30 जून तक जमा कराना था। लेकिन नेट बंदी के कारण से 17087 किसान लोन जमा नहीं करा पाए। जिसके कारण 58 करोड 23 लाख 77 हजार एक सौ उनचालीस रुपए अल्पकालीन ऋण जमा नहीं हो पाया। जिस पर दो करोड दस लाख पिचेत्तर हजार आठ सौ चार रुपए ब्याज और पेनल्टी लग गई है। बैंकों के ऑनलाइन सिस्टम में 30 जून की आखिरी तिथि को लोन जमा नहीं होने पर किसानों के खातों में 7 फ़ीसदी ब्याज के साथ 2 प्रतिशत पेनल्टी भी जोड दी गई है। ऐसे में अभी किसान बकाया जमा कराने वाले किसानों को

- **नेटबंदी से लगभग 58 करोड़ 23 लाख 77 हजार एक सौ उनचालीस रुपए अल्पकालीन ऋण जमा नहीं हो पाया**

9 फ़ीसदी ब्याज के साथ लोन की रकम जमा करानी पड रही है। दूसरी ओर बैंकों का तर्क है कि सरकार के आदेश को अपैक्स बैंक सिस्टम में लाएगा उसके बाद स्वत ही ब्याज व पेनल्टी कम हो जाएगी। नेटबंदी की वजह से किसान अल्पकालीन फसली ऋण जमा नहीं करवा पाए। ऐसे में अब बैंकों को आदेश मिलने में देरी की वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा हैं। साथ ही खरीफ की फसल के लिए भी परेशानी सामना करना पड रहा हैं।

अभी तक नहीं आए लिखित आदेश : एमडी

जिले के करीब 17000 किसान लोन जमा नहीं करा पा रहे हैं। सहकारी बैंक अब भी किसानों से लोन जमा करते समय सात प्रतिशत ब्याज ले रहे हैं। जबकि सरकार के निर्णय के अनुसार किसान को ब्याज और पेनल्टी नहीं देनी है। सहकारी बैंक की एमडी सुमन कुमारी का कहना है कि उनके पास अभी सरकार का आदेश नहीं आया है। झुंझुनूं जिले के सहकारी बैंकों व समितियों ने 84023 किसानों को ब्याज मुक्त फसली लोन दिया था। जिसे जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 जून थी। लेकिन 29 जून को राज्य में नेट बंदी लागू होने से किसान समय पर ऋण जमा नहीं करा पाए। इसमें जिले के 17087 किसान हैं। सरकार ने ऋण जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी है। लेकिन सहकारी बैंकों को अभी तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

स्कूलों को क्रमोन्नत किया, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं लगाये

कार्मिकों की भर्ती करवाने की मांग, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने सीएम को पत्र भेजा

बीकानेर, (कासं)। राज्य के सरकारी प्रावि., उप्रावि तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नवीन पद स्वीकृत करने तथा पूर्व से स्वीकृत रिक्त पदों पर कार्मिकों की भर्ती करवाने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा।

संगठन के प्रदेश महामंत्री महेन्द्र कुमार लखारा व प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य ने बताया कि वर्तमान में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं है। वहीं अधिकांश उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं है। ऐसे में विद्यालय में सहायक कर्मी से जुड़े काम किससे करवाये जाएं बड़ी दुविधा बनी हुई है।

संगठन के प्रदेशाध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि वर्तमान में 1200 रूपये प्रतिमाह पर विद्यालय

- **प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्वीकृत ही नहीं है**

कोष से सफाईकर्मी रखा जा सकता है किन्तु प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विकास कोष ही नहीं होता है। यदि छात्र कोष में बजट उपलब्ध भी हो तब भी मात्र 1200 रुपये में कोई भी काम करने को तैयार नहीं होता ।

संगठन के प्रदेश सभाध्यक्ष अरविन्द व्यास एवं प्रदेश संगठन मंत्री प्रहलाद शर्मा ने कहा कि राज्य में प्रावि, उप्रावि तथा उमावि की कुल संख्या तकरीबन 64553 है। तथा इन विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 25348 पद स्वीकृत है। जिनमें से करीब 6649 पदों पर ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है जो कुल स्वीकृत पदों के केवल 26 प्रतिशत है।

प्रदेश उपाध्यक्ष ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि यदि प्रत्येक विद्यालय में एक ही चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की नियुक्ति की जाये तो कुल-64553 कार्मिकों की आवश्यकता होगी। संगठन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सम्पतसिंह एवं प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य ने बताया कि विद्यालयों में जमादार के करीब 456 स्वीकृत पदों पर तकरीबन 113 जमादार कार्यरत है। ऐसे में स्पष्ट है कि भारी मात्रा में पद रिक्त हैं व काम शिक्षकों अथवा बालकों की सहायता से पूरे किए जा रहे हैं।

संगठन की प्रदेश महिला मंत्री जयमाला पानेरी एवं प्रदेश मंत्री अरूण कुमार व्यास के अनुसार पूर्व से स्वीकृत पदों में भी तकरीबन 75 प्रतिशत पद रिक्त है।

'अनाज मंडी में किसानों की सुविधाओं पर फड़ अधिकारी के चेहते व्यापारियों का कब्जा'

किशनगढ़ बास, (निसं)। किशनगढ़ बास में अधिकारियों की आंखों के सामने व्यापारी अनाज मंडी में बने किसानों के कॉमन फड पर अपना अधिकार जमाए

- **कैमरे सालों से खराब, मुख्य गेट के सामने भरा रहता है पानी**
- **अधिकारियों की अनदेखी व्यापारियों और किसानों के लिए बनी सिर दर्द**

किशनगढ़ बास अनाज मंडी के मुख्य गेट पर भरा पानी।

हुए हैं। लाखों की लागत से लगी मास्ट लाइट व कैमरे सालों से खराब पडे है, गेट पर पानी भरा रहता है।

अनाज मंडी में किसानों की फसल को बारिश धूप से बचाकर रखने के लिए सरकार ने अलग से फड़ की व्यवस्था की है, आराम करने के लिए एयर कंडीशन भवन का निर्माण किया है। लाखों की मास्ट लाइट कैमरे लगाए गए हैं लेकिन मंडी में उल्टा ही हो रहा है यहां मंडी सचिव की शह पर किसानों के लिए बने कॉमन फड पर कुछ चेहते व्यापारी गोदाम के रूप में अपना डेरा जमाएं हैं।

कॉमन फड पर अधिकारी के चेहते व्यापारियों का इतना अधिक माल होता है की किसानों को बारिश में भी कॉमन फड पर फसल रखने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। जिसके कारण खुले आसमान के नीचे बारिश में किसानों की फसल खराब हो जाती है और औने पौने दामों में किसानों को बेचकर जाना पडता है।

सरकार ने अनाज मंडी में एक एयर कंडीशनर हॉल का निर्माण किया हुआ है। उसका हॉल का फायदा भी किसानों नहीं मिल रहा है। इन दिनों अनाज मंडी में किसान सरसों की फसल लेकर पहुंच रहा हैं। मंडी टैक्स से सरकार को लाखों का राजस्व मिलने वाला है। मंडी सचिव की अनदेखी के कारण अनाज मंडी प्रांगण में लंबे समय से स्ट्रीट लाइट कैमरे खराब पडे है।

अमरनाथ यात्रा त्रासदी के प्रत्यक्षदर्शी पहुंचे जोधपुर

जोधपुर, (कासं)। अमरनाथ यात्रा त्रासदी के प्रत्यक्षदर्शी चांदपोल निवासी गोपाल देवड़ा और उनके साथ गए हुए यात्री आज वापस दो बसों में जोधपुर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शी गोपाल देवड़ा ने बताया कि 08 जुलाई शुक्रवार के दिन जोधपुर के यात्रियों को यात्रा की अनुमति मिली , सुबह 4 बजे सभी यात्री बालताल से अमरनाथ पवित्र गुफा कि तरफ़ बड़े और शाम को 5 बजे अमरनाथ महादेव के दर्शन कर लिए । वहां उस समय आरती की तैयारी चल रही थी। जोधपुर के तमाम यात्रियों ने वापस बालताल चलने का निर्णय लिया। ठीक उसी वक्त पवित्र गुफा के पास पहाड़ी के ऊपर से बादल फटने की वजह से जल का बड़ा सैलाब आया । इसमें बहुत बड़े- बड़े पत्थर तिनके की तरह बहते हुए नजऱ आए। हम लोगों ने गुफा की सीढ़ियों से देखा कि जिस रास्ते से हम सभी यात्री आए थे वह पुरी तरह से विलुप्त हो चुका था। और जिन टेन्टों में लोग ठहरे हुए थे। वो भी पानी में बह रहे थे। कई यात्री बह गए थे। कई घायल हो गए तो कई यात्री तो सैलाब में दब गए ।

मैडिकल स्टाफ के एप्रेन से लेकर बेडशीट तक खादी के होंगे

बीकानेर, (कासं) देश के मेडिकल कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में खादी के वस्त्रों की खरीद होगी। नेशनल मेडिकल कमीशन (राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग) ने एक आदेश जारी कर चिकित्सकीय पेशे से जुड़े डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ सहित मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में खादी के वस्त्रों का उपयोग करने की सलाह दी है। मेडिकल एजुकेशन बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. अरुणा वी. वनिकर ने कहा कि यह वैज्ञानिक तौर से प्रमाणित हो चुका है कि खादी के वस्त्र और अन्य उत्पाद स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होते हैं।

ऐसे में खादी द्वारा उत्पादित वस्त्र जो विशेष रूप से चिकित्सा पेशेवरों के लिए डिजाइन और निर्मित किए जाते हैं, जैसे बेड-शीट, पिलो कवर, एप्रन, पर्दे, रोगी का गाउन, साबुन, हैंड-वॉश, फेनिल आदि की खरीद कर उनका उपयोग किया जाए। इससे खादी और

- **खादी को सरकारी अस्पतालों का सहारा**

ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत तैयार करवाए जा रहे हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री और विपणन को बढ़ावा मिलेगा।

देश के विभिन्न कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआई) हॉस्पिटल में फिलहाल खादी के वस्त्रों की खरीद की जाती है। मेडिकल कॉलेज बीकानेर और इससे संबद्ध हॉस्पिटल में अगर खादी के वस्त्रों की खरीद की जाती है तो इसका सीधा लाभ बीकानेर के करीब 12 हजार कतिन और 300-400 बुनकरों को होगा। -शिशुपाल, संभाग अधिकारी राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बीकानेर का कहना है कि नेताओं की पहुंच तक सीमित रही खादी पिछले कुछ सालों में लोकल से ग्लोबल हो चुकी है। इसका सालाना टर्नओवर पूरे देश में एक लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है।

5 बाल अपचारी छत के गेट को तोड़ फरार

टोंक, (निसं)। टोंक के राजकीय सम्प्रेषण गृह में उस समय हड़कंप मच गया जब सम्प्रेषण गृह से बुधवार को दोपहर में 5 बाल अपचारी छत के गेट को तोड़ फरार हो गए।

घटना की सूचना सम्प्रेषण गृह अधीक्षक ने सदर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज देखे। दरअसल बाल सम्प्रेषण गृह के रामप्रसाद ने बताया कि हत्या जैसे जघन्य मामलों में विधि से संघर्षरत एक बाल अपचारी सहित 5 बाल अपचारी छत के गेट को तोड़ कर बाल सम्प्रेषण गृह की दीवार को फांद कर जंगलों के रास्तों से फरार गए। वहीं इस दौरान कुछ बाल अपचारियों के कपड़े और चप्पल भी भागते हुए मौके पर ही छूट गए हैं। पुलिस पांचों बाल अपचारियों की सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखकर तलाश में जुटी हुई है।

अस्पताल की मोर्चरी में फिर बदले शव

जोधपुर, (कासं)। एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी में पुलिस और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते आज एक पखवाड़ा बाद ही शव बदलने की दूसरी घटना हो गई।

प्राप्त जानकारी अनुसार रोहित निवासी रामेश्वर नाबरिया (52) पुत्र नारायण नाबारिया की एमडीएम अस्पताल में कल शाम को मौत हो गई थी। परिजनों ने पोस्टमार्टम और अग्रिम कार्यवाही के लिये शव एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जबकि राईकाबाग बच्चन निवास होटल के पास रहने वाले मानसिंह (32) पुत्र भंवरसिंह राजपूत ने आज सुबह दम तोड़ा जिसका शव भी पोस्टमार्टम के लिये मोर्चरी में रखवाया गया। इसी दौरान जल्दबाजी में रामेश्वर नाबरिया का पोस्टमार्टम कर दिया और उनको मानसिंह बताते हुए शव पैक करके परिजनों को सुपुर्द करने पर परिजन एम्बूलेंस में डालकर घर ले गये। इसी दौरान रामेश्वर नाबरिया के परिजनों ने शव देने को कहा तो पता लगा कि मानसिंह की जगह रामेश्वर नाबरिया का शव लेकर चले गये है और मानसिंह का शव फ्रिज में ही पड़ा है। बाद में मानसिंह की जगह रामेश्वर नाबरिया का शव राईकाबाग छोडक़र एम्बूलेंस चालक वापस आया।

नीमराणा में नवीन कॉलेज खोलने की घोषणा के बाद भी नहीं मिल रहा अस्थाई भवन

बहरोड़/नीमराना, (निसं)। औद्योगिक क्षेत्र नीमराणा में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की राज्य सरकार की बजट सत्र 2022- 23 में घोषणा के बाद नीमराणा महाविद्यालय के नाम से प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया आरंभ की गई। जिसकी ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाते हुए 16 जुलाई 2022 कर दिया गया परंतु अजीबोगरीब स्थिति देखने को यह मिली कि आज तक अस्थाई भवन उपलब्ध नहीं हो पाया है।

- **कॉलेज में ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाते हुए 16 जुलाई 2022 कर दिया गया है**

आयुक्तालय के द्वारा स्थानीय प्रशासन जिसमें सीबीईओ सरिता , उपखंड अधिकारी मुकुट सिंह नीमराणा तथा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए राजकीय उच्च स्तर तक के विद्यालय होने के बावजूद नीमराणा में महाविद्यालय के छात्रों के लिए अस्थाई भवन की व्यवस्था नहीं होने के कारण कागजों में ही राजकीय महाविद्यालय नीमराना के चलने की स्थिति सामने आई है।

नीमराणा उपखंड अधिकारी मुकुट सिंह से जानकारी लेने ने पर उन्होंने बताया कि महाविद्यालय के लिए अस्थाई भवन की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है । जल्द ही किसी आईटीआई भवन के मामले में बात चल रही है । वहीं नीमराणा सरपंच माया के प्रतिनिधि शिवचरण गुप्ता ने बताया कि उनसे राजकीय महाविद्यालय की अस्थाई भवन उपलब्धि के मामले में कोई मांग या सहयोग करने की बात नहीं आई है तथा बहरोड़ महाविद्यालय जिस प्रकार हायर सेकेंडरी विद्यालय भवन से क्रियाशीलता में आया था उसी प्रकार नीमराणा में भी चलाया जा सकता है । उन्होंने बताया कि महाविद्यालय के लिए 25 बीघा जमीन के अलॉटमेंट की एनओसी जारी कर भरपाई हेतु अन्यत्र जमीन की व्यवस्था कर दी गई है। जिसका निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत किया जाएगा।

करंट लगने से खलासी की मौत

सादुलपुर, (निसं)। एन.एच. 52 चूरू सादुलपुर सडक मार्ग पर होटल पर खडे ट्रक का रस्सा टाईट करते समय चालक द्वारा अचानक ट्रक को चलाने से खलासी की करंट लगने से मौत हो गई।

थानाधिकारी कृष्ण कुमार बलोदा नें बताया कि शिशपाल सिंह राजपूत निवासी गाँव सेऊवा तहसील राजगढ जिला चूरू नें इस आरोप का मामला दर्ज करवाया है कि 24 जून को उसका भाई विजेन्द्र सिंह ट्रक बतौर खलासी के रूप में ट्रक में सामान भरकर गुजरात से हरियाणा जा रहे थे।

राजगढ एनएच 52 पर बने शहीद भगतसिंह होटल के पास पहुंचे तो टायरों के रस्से ढिले हो रहे थे। जिस कारण उसका भाई समय करीबन 2 बजे ट्रक के ऊपर चढकर टायरों के रस्सों को टाईट कर रहा था। जैसे ही वह ट्रक पर चढकर रस्से को खींचने लगा तो इतने में ही ट्रक चालक रणवीर सिंह ने अपने ट्रक को अचानक लापरवाही पूर्वक चला दिया। जिससे उसके भाई का शरीर अनियंत्रित हो गया और ऊपर से गुजर रही लाईन के विद्युत तारों से टकरा गया एवं करंट लगने से उसके भाई की ट्रक के ऊपर ही मृत्यू हो गई। परिवाादी ने बताया कि घटना के समय उसने पुलिस को रिपोर्ट दी थी।

400 बच्चों में से इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे 255, बाकी को नहीं मिला एडमिशन

ग्रामीणों का कहना है कि दो पारियों में चलाया जाए स्कूल

श्रीगंगानगर, (कासं)। जिले के गांव दुल्लापुर केरी में पिछले दिनों राज्य सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने की घोषणा की थी। इससे ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्हें लगा था कि अब उनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूल में पढ़ सकेंगे। उनकी यह खुशी तब गायब हो गई जब अंग्रेजी मीडियम होने के बाद स्कूल में निर्धारित संख्या में ही छात्रों को प्रवेश दिया गया।

स्कूल में करीब चार सौ स्टूडेंट्स पिछले सेशन में पढ़ रहे थे। अब महात्मा गांधी स्कूल बनने पर इनमें केवल 255 को ही प्रवेश दिया गया है। बाकी बचे डेढ़ सौ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। गांव के सरकारी स्कूल को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने और अब इसमें सभी स्टूडेंट्स को प्रवेश नहीं मिलने से एडमिशन से वंचित रहे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने रोष जताया। उन्होंने स्कूल का घेराव कर लिया। इनका कहना था कि राज्य सरकार ने स्कूल को इंग्लिश मीडियम घोषित किया है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के 400 बच्चे पढ़ रहे थे। इनमें 255 बच्चों को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दिया गया है। बाकी बचे स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए गांव के बाहर अन्य स्कूलों में जाना होगा।

ग्रामीणों ने डीईओ के नाम ज्ञापन भी प्रिंसिपल मुकंदसिंह को सौंपा। दुल्लापुर केरी के ग्रामीणों का कहना था कि या तो सभी बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिला दिया जाए या इसी स्कूल को दो पारियों में चलाया जाए। ग्रामीणों का कहना था कि अगर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो तालाबंदी की जाएगी।

विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में संचालित करने का विरोध

बीदासर, (निसं)। राजकीय बांठिया सीनियर विद्यालय बीदासर को राज्य सरकार द्वारा नये सत्र से कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम मे संचालन करने के विरोध में अभिभावकों व विद्यार्थियों ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया।

अभिभावकों ने बताया कि अधिकतर विद्यार्थी हिन्दी माध्यम से ही अध्ययन करना चाहते है। जो बच्चे शुरू से ही हिन्दी माध्यम से पढ रहे हैं उनको ऐसे बीच मे अंग्रेजी माध्यम में करना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अभिभावकों का कहना है कि अब किसी राजकीय विद्यालय में हिन्दी माध्यम में प्रवेश भी दिलायें तो सभी राजकीय विद्यालयों में नामांकन अधिक है तथा पास में कोई सरकारी विद्यालय नहीं है। इस मौके पर दर्जनो लोगों ने विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के होने का विरोध किया।

मामले को लेकर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुखदेवाराम प्रजापत ने कहा कि अभिभावकों का विरोध करना गलत है उन्हें कुछ लोगों द्वारा भ्रमित किया जा रहा है ऐसी कोई बात नहीं है राजकीय बांठिया विद्यालय में अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मिडियम दोनों विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाऐंगे तथा हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों श्रेणी के विद्यार्थियों को दो पारियों में अध्ययन करवाया जाएगा।

प्रधानाध्यापक ओमप्रकाश शर्मा का कहना है कि विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ ने वाला एक भी अध्यापक नहीं है। विद्यालय में हिन्दी माध्यम से पढ़ ने वाले अध्यापकों द्वारा ही अंग्रेजी माध्यम से संचालन किया जा रहा है।

10 हजार रुपए की नौकरी के लिए भर गया रोजगार कार्यालय

अलवर, (निसं)। बेरोजगारी की तस्वीर विकट हो चुकी है। 10 हजार रुपए के वेतन वाले 9 पद के लिए सैकडों युवक-युवती बुधवार को अलवर के जिला रोजगार कार्यालय पहुंच गए। जहां 9 पदों के लिए इंटरव्यू लिए गए। सूचना केवल राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी

- **बुलानी पड़ी दो और कंपनियां, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर के इंटरव्यू**

अलवर के रोजगार कार्यालय में बेरोजगारों को भीड़ उमड़ी।

मानवाधिकार नेशनल टाइगर फोर्स ट्रस्ट नई दिल्ली की ओर से जारी की गई थी कि इनके जरिए ब्लॉकवार को-ऑर्डिनेटर लगाए जाएंगे। जिले में 9 ही पद हैं।

कॉर्डिनेटर पद के लिए योग्यता भी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा आरएससीआरटी रखी है। इसके बावजूद एक-एक ब्लॉक से 50 से अधिक बेरोजगार आ गए। जिनमें कई एमए, इंजीनियरिंग व अन्य डिग्री धारी भी शामिल थे। जिला रोजगार अधिकारी को एक दिन पहले ही अंदेशा हो गया था कि भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी मानवाधिकार नेशनल टाइगर फोर्स ट्रस्ट नई दिल्ली की ओर से केवल एक ब्लॉक में एक ही कॉर्डिनेटर लगाया जाएगा। बेरोजगार ज्यादा आ सकते हैं। इस कारण दो-तीन और कंपनियों को बुला लिया ताकि उनमें चयन हो सके। यहां सिक्योरिटी सर्विसेज की ओर से भी युवाओं का चयन किया गया है। वहीं एलआईसी के एजेंट बनने के लिए भी आवेदन लिए गए हैं। 10 हजार रुपए की नौकरी पाने की इस दौड में एक-दो गर्भवती महिलाएं भी मौजूद थी । ज्यादातर को-ऑर्डिनेटर बनने के लिए इंटरव्यू देन आए थे। ब्लॉक वार इंटरव्यू लिए गए हैं। जिला रोजगार अधिकारी श्यामलाल साटोलिया ने कहा कि को-ऑर्डिनेटर के पद केवल 9 हैं। बेरोजगार अधिक आए, इस कारण दो-तीन दूसरी कंपनी बुलाई गई।

रास्ता खुलवाने एवं सुरक्षा की मांग को लेकर कलेक्टर से फिर मिला दलित परिवार

मुंडावर तहसील के गांव सुखमनहेड़ी में जाति विशेष के दबंगों द्वारा प्रताड़ित करने का मामला

अलवर, (निसं)। दलित शोषण मुक्ति मंच के प्रदेश सहसंयोजक डॉ. रमेश बैरवा एवं जिला संयोजक एडवोकेट बी एल वर्मा के नेतृत्व में मुंडावर तहसील के गांव सुखमनहेड़ी के पीड़ित दलित परिवाजन और मंच कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मुंडावर तहसील के गांव सुखमनहेड़ी में जाति विशेष के दबंगों द्वारा अवरुद्ध किए दलित परिवार के घर और खेतों के रास्ते को अविलंब खुलवाने और मारपीट की धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

ज्ञापन में लिखा है कि 4 जुलाई को भी पीड़ितों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने तत्कालीन जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था आश्वासन के बाद दिया आज तक भी उचित कार्यवाही नहीं की गई ।

घर से निकलने का रास्ता बंद हो जाने से पीड़ित परिवार के बच्चे स्कूल और कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। पीड़ितों ने कलेक्टर को वीडियो क्लीपिंग दिखाकर अपने बुरे हालातों के बारे में बताया। जिला कलेक्टर ने जल्द उचित कार्यवाही आश्वासन दिया है।

पीड़ित परिवार व दलित शोषण मुक्ति मंच के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मिल सुरक्षा की गुहार लगाई।

- **जाति विशेष के दबंगों द्वारा अवरुद्ध किए दलित परिवार के घर और खेतों के रास्ते को खुलवाने और धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग**

इस अवसर पर पीडित दलित परिवार के श्रीचंद, हरचंद एवं फूलचंद एवं इनके परिवारजन, ग्रामीण सहित डीएसएमएम से जुड़े कार्यकर्ता सहित महिलाएं भी शामिल रहीं।